(iv) Trained elephants are mostly used for showing wildlife to the tourists inside the park area.

(v) Tourists are advised not to throw garbage in Ramganga river. They are advised to carry back with them, the non bio-degradable litter from the park area.

Consumption of forest wood by Ballarpur Paper Industries

2447. SHRI G. PRATHAPA REDDY: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) how much forest wood from the forests of Maharashtra and bordering Andhra has been consumed by the Ballarpur Paper Industries in Chandrapur and the adjoining areas;

(b) at what rate is the wood being supplied to them for the last three years;

(c) on what consideration the wood is supplied to them at a cheap rate; and

(d) whether Government would reconsider its policy in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) As per the reports received from State Forest Departments of Maharashtra and Andhra Pradesh, no forest wood is being supplied to the Ballarpur Paper Industries from the forests of Maharashtra and bordering Andhra Pradesh from the supply year 1991-92 onwards. However, Government of Maharashtra had agreed to make supply of mixed hard-wood to Ballarpur Paper Industries upto the extent of 60,000 Metric Tonnes per year for a period of 20 years from 1971 to 1991 to help the Mills to meet their increasing demands of raw material. The said quantity was later amended to 36,000 Metric Tonnes per year with effect from 14th April, 1978.

(b) to (d) Do not arise.

उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण संबंधी मानदण्डों का पालन न किया जाना

2448. **श्री मूलचन्द मीणा:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु और बड़े उद्योग प्रदूषण नियंत्रण संबंधी विनियमों का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा राज्य-वार क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या सरकार की उद्योगों को स्वच्छ प्रौद्योगिकी और आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस योजना के अंतर्गत अब तक राज्य-वार कितनी सहायता उपलब्ध करायी गई है; और

(च) क्या मध्य प्रदेश में रायपुर के निकट "केड़िया डिस्टेलरी" तथा शहडोल के निकट "ओरियन्ट पेपर मिल्स" के विरुद्ध अनेकानेक शिकायतें मिलने के बावजूद उनके द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित करना बरकरार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) बड़े और मझौले उद्योगों की 17 श्रेणियों के तहत 1551 यूनिटों की शिनाख्त की गई है, जिनमें से 1125 यूनिटों के निर्धारित प्रदूषण नियंत्रण मानकों के अनुपालन के लिए पर्याप्त सुविधाएं लगा ली हैं। तथापि, बड़ी संख्या में छोटी यूनिटें वित्तीय अभावों, प्रदूषण नियंत्रण के लिए तकनीकी ज्ञान की कमी और कुछ मामलों में प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं स्थापित करने के लिए स्थान की कमी के कारण उत्सर्जन और बहिस्रावों के निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं कर पा रही है।

(ख) सरकार ने छोटी यूनिटों में सस्वच्छ प्रौद्योगिकी और अपशिष्ट के पुनर्प्रयोग और पुनश्चक्रण की पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए उपाय शुरू कर दिये हैं। छोटे पैमाने के उद्योगों में अपशिष्ट न्यूनीकरण के लिए क्षेत्र विशिष्ट मैनुअल तैयार करने के वास्ते पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को एक परियोजना प्रायोजित की गई है। छोटे पैमाने के उद्योगों में अपशिष्ट न्यूनीकरण के लिए एक मार्गदर्शिका तैयार की गई है। सरकार द्वारा "छोटे पैमाने के उद्योगों के समूहों में अपशिष्ट न्यूनीकरण सर्किल्स स्थापित और संचालित